

ep-207

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर

निगरानी 146-I-15

मुसं विद्याबाई पृत्री जंगी पटेल पति व्हा गोपाल पटेल

निवासी-ग्राम बिलहरा, तह. व जिला पन्ना

... आवेदिका

॥ विरुद्ध ॥

म.प. शासन

द्वारा-क्लेक्टर पन्ना, तह. व जिला पन्ना ... अनावेदक

पु० क०

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प. भू. रा. संहिता

आवेदिका निम्नलिखित प्रार्थना करती है:-

आवेदिका अतिरिक्त कमिश्नर सागर द्वारा पु. कं. 1383/अ-19

/96-97 में पारित आदेश दिनांक 29.6.06 के विरुद्ध यह

निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

संक्षिप्त तथ्य-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आराजी नं. 189 जुज रकवा

1.20 हेक्टेयर व आराजी क्रमांक 466 रकवा 0.80 हेक्टेयर भूमि स्थित

ग्राम बिलहरा तह. व जिला पन्ना आराजी म.प. शासन की भूमि थी

जिस पर आवेदिका का सन् 1979-1980 से वृक्ष लगाकर अतिक्रमण के

रूप में लगातार कब्जा किये गयी आ रही है आवेदिका एक आदिवासी

महिला है। अतिक्रमण किये जाने के कारण व विवादित भूमि पर

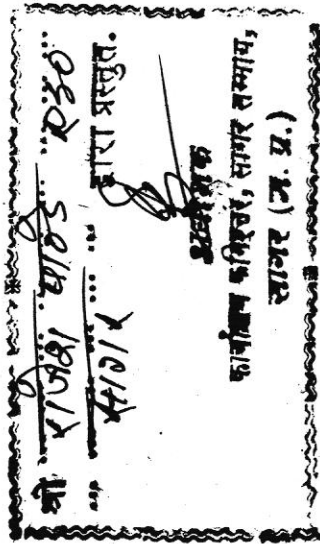
आवेदिका के वृक्ष लगे होने के कारण नायब तहसीलदार पन्ना द्वारा

रा.प. कं. 4अ-61/वर्ष 86-87 में पारित आदेश दिनांक 29.8.87 द्वारा

आराजी नं. 189 रकवा 0.80 हेक्टेयर में वृक्ष लगाने हेतु विधिपूर्वक पट्टा

B.O.R.

2 JAN 2015



165  
02-01-15

सागर

15-1-15

16-1-15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

30

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 146-एक/2015

जिला पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 11-03-2015       | <p>आवेदक अधिवक्ता को कायमी के बिन्दु सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1383/अ-19/1996-97 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29-9-2006 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक द्वारा कायमी के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 29-9-06 का अवलोकन किया । अपर आयुक्त अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह स्पष्ट किया है कि उनके न्यायालय में कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 1009/डोइट/1995 में पारित आदेश दिनांक 28-7-95 का कोई आदेश नहीं है बल्कि पृष्ठांकन क्रमांक है जिसकी नकल भी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में बिना प्रतिलिपि के प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की गई है । अपर आयुक्त द्वारा पारित उपर्युक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है।</p> |  |

  
प्रशासकीय सदस्य